INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

HANDWRITTEN NOTES

बिहार पुलिस

बिहार उपनिरीक्षक

BIHAR POLICE SUBORDINATE SERVICES COMMISSION

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

भाग-4 भारत + बिहार की अर्थव्यवस्था

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

बिहार उपनिरीक्षक (SI)

BIHAR POLICE SUBORDINATE SERVICES COMMISSION

भाग – 4

भारत + बिहार की अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**बिहार पुलिस उपनिरीक्षक (SI)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को BIHAR POLICE SUBORDINATE SERVICES COMMISSION (BPSSC)" द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**बिहार पुलिस उपनिरीक्षक (SI)**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/paxqem

Online Order करें - https://shorturl.at/hitzF

मूल्य : ₹ 680

संस्करण : नवीनतम (2023-24)

क्र. सं	अध्याय	पेज न.
	भारतीय अर्थव्यवस्था	
1.	अर्थव्यवस्था एक परिचय	1
2.	राष्ट्रीय आय	4
3.	बैंकिंग	11
4.	राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ	28
5.	संवृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान	30
6.	लोक वित्त	32
7.	भारतीय बजट	36
8.	मुद्रास्फीति – अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र	46
9.	भारतीय कृषि क्षेत्र	51
10.	औद्योगिक क्षेत्र	61
11.	मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास	67
12.	गरीबी, बेरोजगारी एवं नई शिक्षा नीति	71
13.	केंद्र सरकार की योजनाएँ	82
	बिहार की अर्थव्यवस्था	
1.	अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन	86

2.	राजकीय वित्त व्यवस्था	९1
3.	कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र	९५
4.	उद्यम क्षेत्र	101
5.	श्रम, रोजगार तथा कौशल	106
6.	भौतिक अधिसंरचना	110
7.	ई-शासन	112
8.	ऊर्जा क्षेत्र	121
9.	ग्रामीण विकास	124
10.	नगर विकास	128
11.	बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र	131
12.	मानव विकास	134
13.	बाल विकास	146

अर्थशास्त्र

अध्याय – I

अर्थव्यवस्था एक परिचय

परिचयः-

- Economics (अर्थशास्त्र) शब्द एक Greek word 'Oikonomia' से उत्पन्न हुआ है ।
- Oikonomia शब्द Oikos and Nomos दो शब्दों से मिलकर बना है ।
- Oikos का अर्थ गृह अथवा परिवार जबकि Nomos का का अर्थ है प्रबंधन । अर्थात् Oikonomia गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है ।

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतरः-

अर्थशास्त्र	अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है	अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
अर्थशास्त्र केवल अध्ययन का क्षेत्र है	अर्थव्यवस्था निष्पादन (Execution) की भूमिका निभाती है।
अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है इनकी किताब (The Wealth of nations) मे अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है।	जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं ।
अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं- (i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics) (ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)	अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
	अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यावहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि ।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (Branches of economic)

- अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ है, जो निम्नलिखित है-

(i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics)

(ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)

अर्थव्यवस्था के प्रकारः-

A. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था :-

- जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
- अर्थात् यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है।
- एडम स्मिथ की 'दा वेल्थ ऑफ़ नेशन' पूँजीवाद को दार्शनिक आधार प्रदान करता है।
- अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोपीय देश पूँजीवाद के समर्थक हैं।

पूँजीवाद के फायदे या गुणः-

- पूँजीवाद नवाचार को बढ़ावा देता है।
- पूँजीवाद और समाज दोनों स्वतंत्रता और अवसर पर केंद्रित हैं।
- पूँजीवाद आबादी की जरूरतों को पूरा करता है।
- पूँजीवाद स्व-नियामक है।
- पूँजीवाद समग्र रूप से समाजों की मदद करता है।

पूँजीवाद के नुकसान या दोषः-

- धन और आय के वितरण की असमानता
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य के रूप में कक्षा संघर्ष
- सामाजिक लागत बहुत अधिक है
- पूँजी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता
- बेरोजगारी और रोजगार के तहत
- वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं है।

B. समाजवाद अर्थव्यवस्था

- उत्पादन एवं वितरण के सामूहिक नियंत्रण पर बल देता है।
- राज्य द्वारा विनियमित निजी क्षेत्र की भूमिका से लोक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति।
- भारत,बांग्लादेश,ब्राजील,समेत विकासशील अधिकांश देश समाजवाद के समर्थक हैं।
- बौद्ध और जैन धर्म का अस्तेय आवश्यकता से अधिक संसाधनों के एकत्रीकरण का विरोध करता है, जो समाजवाद की अवधारणा के अनुकूल है।
- अशोक के शिलालेखो से लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती हैं, वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में प्रमाण देता है।

- इसी प्रकार मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण, बेरोजगारों के लिए पेंशन जैसी समाजवादी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।

समाजवाद के पक्ष में तर्क या गुण:-

शोषण का अन्त:-

- समाजवाद श्रमिको एवं निर्धनो के शोषण का विरोध करता है। इसलिये विश्व के श्रमिक किसान निर्धन इसका समर्थन करते है।

सामाजिक न्याय पर आधारित:-

- समाजवादी व्यवस्था में किसी वर्ग विशेष के हितो को महत्व न देकर समाज के सभी व्यक्तियों के हितो को महत्व दिया जाता है यह व्यवस्था पूँजीपतियों के अन्याय को समाप्त करके एक ऐसे वर्गविहीन समाज की स्थापना करने का समर्थन करती है जिसमें विषमता न्यनूतम हो।

उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यक्ता:-

- व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किये जाने वाले उत्पादन के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था में समाजिक आवश्यक्ता और हित को ध्यान में रखकर उत्पादन होगा क्योंकिसमाजवाद इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन हो वह समाज के बहुसख्यक लोगो के लाभ के लिए हो।

उत्पादन पर समाज का नियंत्रण :-

- समाजवादियो का मत है कि उत्पादन और वितरण के साधनो पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करके विषमता को समाप्त किया जा सकता है।
- सभी को उन्नति के समान अवसर
- साम्राज्यवाद का विरोधी

समाजवाद के विपक्ष में तर्क अथवा आलोचना:-

राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि :-

- समाजवाद मे आर्थिक तथा राजनीतिक दोनो क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जायेगा जिसके परिणामस्वरुप राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्य समुचित रुप से संचालित और समपादित नहीं होंगे।

वस्तुओं के उत्पादन में कमी :-

- समाजवाद के आलोचको की मान्यता है कि यदि उत्पादन के साधनो पर सम्पूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति की कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी और कार्यक्षमता भी धीरे धीरे घट जायेगी।
- व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा तो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा घट जायेगी।

समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी :-

- प्रजातंत्र में व्यक्ति के अस्तित्व को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है वही समाजवाद में वह राज्य रुपी विशाल मशीन में एक निर्जीव पूर्जा बन जाता है।

नौकरशाही का महत्व :-

- समाजवाद में राज्य के कार्यो में वृद्धि होने के कारण नौकरशाही का महत्व बढ़ता है। और सभी निर्णय सरकारी कर्मचारियो द्वारा लिये जाते है ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ता है।

C. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) :-

- यहाँ, उत्पादन की कुछ योजनाएँ राज्य द्वारा सीधे या इसके राष्ट्रीयकृत उद्योगों के माध्यम से शुरू की जाती है, और कुछ को निजी उद्यम के लिए छोड़ दिया जाता है।
- इसका अर्थ है कि समाजवादी क्षेत्र (यानी सार्वजनिक क्षेत्र) और पूँजीवादी क्षेत्र (यानी निजी क्षेत्र) दोनों एक-दूसरे के साथ हैऔर एक-दूसरे के पूरक है।
- इसे बाजार की अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बीच आधे घर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। इसलिए, इस प्रकार कीअर्थव्यवस्था पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदे:-

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन :-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करता है और इसे बढ़ने का उचित अवसर मिलता है।
- यह देश के भीतर पूंजी निर्माण में वृद्धि की ओर जाता है।

स्वतंत्रता:-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक और व्यावसायिक दोनों तरह की स्वतंत्रता है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है।
- इसी तरह, हर निर्माता उत्पादन और खपत के संबंध में निर्णय ले सकता है।

संसाधनों का इष्टतम उपयोग:-

- इस प्रणाली के तहत, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए काम करते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक लाभ के लिए काम करता है जबकि निजी क्षेत्र लाभ के अधिकतम करण के लिए इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग करता है।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector):-

- इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है।
- इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है; जैसे - व्यापार, होटल, भण्डारण, बीमा, व्यापार।

परीक्षोंपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जबकि मध्यप्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था है ।
- भारत एक विकासशील देश है।
- बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आयात एवं निर्यात बिल्कुल संभव नहीं है ।
- खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना प्रतिबंध के वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है ।
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वतंत्र रूप से होता है ।
- व्यवसायिक बौद्धिक पूँजी के स्वामित्व को ट्रेड मार्क कहा जाता है ।
- निर्माण एवं विनिर्माण वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र,वानिकी मत्स्यन तथा खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।
- वर्ष 1776 में एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' थी ।
- बैंकिंग बीमा चिकित्सा शिक्षा पर्यटन आदि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं ।
- भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ से आधिक्य की स्थिति रहती है ।

> **NOTE-** अमेरिकी थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। वर्ष 2018 में भारत 7वें नंबर पर था।

अध्याय – 2
राष्ट्रीय आय

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों , चाहे वे निवासी हों या अनिवासी द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) कहा जाता है।
- इसी प्रकार देश के सामान्य नागरिकों द्वारा विदेशों में की गई मूल्य वृद्धि संबंधित देश के सकल घरेलू उत्पाद का भाग है ।

एक देश की घरेलू सीमा

- ✓ एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित (Factor Income) को घरेलू आय (अथवा घरेलू उत्पाद) कहा जाता है । अतः हमें घरेलू सीमा की अवधारणा को अवश्य समझ लेना चाहिए ।
- ✓ आम बोलचाल की भाषा में एक राष्ट्र की घरेलू सीमा का अर्थ देश की राजनीतिक सीमाओं (Political Frontiers) के अंदर के भू - भाग (Territory) से लिया जाता है परन्तु राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में घरेलू सीमा शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जाता है ।
- ✓ **इससे निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है**
  (1) राजनीतिक सीमाओं का भू - भाग जिसमें देश की सामुद्रिक सीमा भी सम्मिलित होती है ।
  (2) देश के निवासियों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में चलाए जाने वाले वायुयान तथा जलयान । उदाहरण के लिए , जापान तथा कोरिया के बीच नियमित रूप से चलने वाले भारतीय जलयान अथवा इंग्लैण्ड और कनाडा के बीच एयर इंडिया द्वारा चलाए जाने वाली हवाई जहाज भी भारत की घरेलू सीमा के ही अंग हैं ।
- ✓ मछली पकड़ने की नौकाएँ , तेल व प्राकृतिक गैस यान (Rigs) तथा तैरते हुए प्लेटफार्म (Floating Platforms) जो अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा में या उस सीमा में देश के निवासियों द्वारा चलाए जाते हैं जिनमें दे को तेल खोजने का एकमात्र (Exclusive) अधिकार है । उदाहरण के लिए भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने की नौकाओं को हिंद सागर के अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग में चलाना , भारत की घरेलू सीमा का अंग है । उपरोक्त नोट इस स्थिति में भी लागू होता है।
- ✓ एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास , वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान । उदाहरण के लिए , अमेरिका में भारतीय दूतावास , भारत की घरेलू सीमा का अंग है तथा भारत में अमेरिका का दूतावास अमेरिका की घरेलू सीमा का अंग है ।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)

- शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product) ज्ञात करने के लिए GDP में से पूँजी स्टॉक की खपत (मूल्य ह्रास) को घटाना होता है ।
- गणितीय समीकरण के रूप में , **NDP = GDP = Depreciation**
- **बाजार कीमत तथा कारक (साधन) लागत की अवधारणा**

➢ राष्ट्रीय आय / राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार कीमत अथवा कारक (साधन) लागत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है ।

➢ बाजार कीमत में व्यक्त राष्ट्रीय आय / उत्पाद (अथवा घरेलू आय / उत्पाद) को बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय (अथवा बाजार कीमत पर घरेलू आय) कहा जाता है ।

➢ इसी प्रकार , कारक (साधन) लागत के रूप में व्यक्त राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है ।

➢ इन दोनों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है बाजार कीमत में दो प्रभाव सम्मिलित होते हैं –

(i) आर्थिक सहायता (Subsidies) का प्रभाव जिसके कारण बाजार कीमत घटती है ।

(ii) अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) का प्रभाव जिसके कारण बाजार कीमत बढ़ती है ।

कारक लागत , आर्थिक सहायता अथवा अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव से मुक्त होती है । तद्नुसार बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय (अथवा घरेलू आय) को कारक लागत पर राष्ट्रीय आय / राष्ट्रीय उत्पाद में बदलने के लिए निम्नलिखित समीकरण की सहायता ली जाती है

- **बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय** - अप्रत्यक्ष कर + आर्थिक = कारक लागत पर राष्ट्रीय आय
- आर्थिक सहायता जो बाजार कीमत को कम करती है इसमें जोड़ी जाती है एवं अप्रत्यक्ष कर जो बाजार कीमत को बढ़ाते हैं इसमें से घटाए जाते हैं ।
- उपर्युक्त समीकरण को निम्नलिखित ढंग से भी लिखा जाता है-

(बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = कारक लागत पर राष्ट्रीय आय)

(शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = अप्रत्यक्ष कर - आर्थिक सहायता)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गयी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है।
- इसका अनुमान घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़कर लगाया जा सकता है ।

(GNP = GDP + X – M)

जिसमें

X = देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय

M = विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय

उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि X = M है, तो GNP = GDP के होगा । इसी प्रकार जब बन्द अर्थव्यवस्था (Closed economy)) के अन्तर्गत X - M = 0 (शून्य) है तो वहाँ GNP GDP होगा।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)

- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक ज्ञात करने के लिए GNP में से पूँजी सटॉक की खपत (मूल्य ह्रास) को घटाना होता है ।
- **गणितीय समीकरण के रूप में-**

(NNP = GNP – Depreciation)

राष्ट्रीय आय (National Income)

- जब NNP का मूल्यांकन अथवा मापन साधन लागत पर किया जाता है, तो उसे ही राष्ट्रीयआय के नाम से जाना जाता है ।
- इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) में से अप्रत्यक्ष करों को घटाना होता है, जबकि सब्सिडी को जोड़ना होता है । इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product at Factor Cost) अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है।

गणितीय समीकरण के रूप में-

▪ **[साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय (NI) = बाजार कीमतों पर NNP- अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी (Subsidy)**

- राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के माँग से होता है । इसमें उन समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है , जो देश के सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अथवा इसके बाहर रहकर उत्पादित की गई है । इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय को भी सम्मिलित किया जाता है। इसे राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है ।
- **राष्ट्रीय आय से संबंधित मुख्य ध्यान देने योग्य बातें हैं-**

1. राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है।
2. इसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है न कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को ।

असमानता निवारण के उपाय (Measures of Eradicate Inequality)

- असमानता निवारण हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए।
- ✓ देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए।
- ✓ भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि का वितरण किया जाए ।
- ✓ प्रत्येक राज्य की विकास दर में समानता लाई जाए।
- ✓ प्रत्येक देश में न्यूनतम मजदूरी का पालन सख्ती से कराया जाए ।
- ✓ कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

राष्ट्रीय आय की गणना का महत्त्व

- राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है , जिससे विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। उपरोक्त जानकारी के माध्यम से नीति निर्माताओं को सटीक व व्यवस्थित योजना बनाने में मदद मिलती है ।
- राष्ट्रीय आय की गणना का महत्त्व इस बात में भी है कि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने व विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताओं का निर्माण किया जाता है ।
- राष्ट्रीय आय की गणना से योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है तथा सरकार के राजस्व प्राप्ति व व्यय का खाका बनाया जा सकता है।

अध्याय – 3

बैंकिंग

- बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं, जो जनता की धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है।
- लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय-समय पर निकालते रहते हैं।
- बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं।

भारत में बैंकिंग

- ➢ भारत में स्थापित पहली बैंक Bank of Hindustan थी इसकी स्थापना Alexandey and Company 1770ई. में की थी कुछ समय बाद यह बैंक बन्द हो गई।
- ➢ इसके बाद देश में निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसीडेंन्सी बैंकों की स्थापना की गई - वर्ष 1806 में बैंक ऑफ बंगाल (Bank of Bengal.) , वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे (Bank of Bombay) तथा वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास (Bank of Madras) ।
- ➢ इन तीनों बैंकों पर बैंक ऑफ मद्रास अपना नियंत्रण रखती थी । बाद में इन बैंकों के कार्यों को सीमित कर दिया गया । वर्ष 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Impe rial Bank of India) की स्थापना की गई और । जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया ।
- ➢ भारत में पहली सीमित देयता वाला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था जिसकी स्थापना फैजाबाद में वर्ष 1881 में की गयी थी ।
- ➢ उसके बाद वर्ष 1894 में लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई जो पहला पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक था ।

भारत में स्थापित प्रमुख बैंक व उनकी स्थापना

बैंक का नाम	स्थापना वर्ष
द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान	1770
बैंक ऑफ बंगाल	1806
बैंक ऑफ बॉम्बे	1840
बैंक ऑफ मुद्रास	1843
इलाहाबाद बैंक	1865
एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला	1881
अवध कॉमर्शियल बैंक	1881
पंजाब नेशन बैंक	1894
बैंक ऑफ इंडिया	1906
पंजाब एंड सिंध बैंक	1908

बैंक ऑफ बड़ोदा	1909
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1911
बैंक ऑफ मैसूर	1913
इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया	1921
भारतीय रिजर्व बैंक	1935
भारतीय स्टेट बैंक	1955

भारतीय रिजर्व बैंक

- भारत का केन्द्रीय बैंक है ।
- वर्ष 1930 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (R.B.I.) की स्थापना RBI अधिनियम, 1934 के तहत् । अप्रैल , 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से हुई थी ।
- 1 जनवरी, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ (1935-37) थे ।
- देश के स्वतंत्रता के समय में RBI के गर्वनर सर सी. डी. देशमुख (1943-49) थे ।
- रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन केन्द्रीय संचालक मण्डल (Central Borad of Directors) द्वारा होता है।
- सम्पूर्ण देश में इसे चार भागों में बाँटा गया है - उत्तरी क्षेत्र , दक्षिणी क्षेत्र , पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र ।
- इसमें प्रत्येक के लिए 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड (Local board) होता है ।
- केन्द्रीय बोर्ड में 1 गवर्नर तथा अधिक से अधिक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार पाँच वर्षों के लिए करती है ।
- वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास (12 दिसम्बर, 2018 से लगातार) है।
- स्थानीय बोर्डों के कार्यालय नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई में है ।
- स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं ।
- रिजर्व बैंक का प्रधान अथवा केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में स्थित है ।
- नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थानीय प्रधान कार्यालय है

RBI के कार्य

भारत में नए नोट जारी करने की व्यवस्था

- एक रुपये के नोट का सभी सिक्कों को छोड़कर रिजर्व बैंक को विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एकाधिकारक प्राप्त है ।
- रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक रुपए के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देशे में वितरण का कार्य करता है ।
- करेन्सी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति (Minimum Reserve System) को अपनाता है। इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋणपत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपये के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य (धातु तथा मुद्रा मिलाकर) 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए । यह पद्धति रिजर्व बैंक ने 1957 के बाद अपनाई थी ।

> - **NOTE**-नए नोट छापने की एक अन्य व्यवस्था भी हैं परन्तु इसका प्रयोग भारत में नहीं होता यह व्यवस्था अनुपाती आरसी व्यवस्था है (Prahetional Resere system) इसके अन्तर्गत जिस अनुपात में नए नोट का मूल्य बढ़ता हैं उसी अनुपात में रखे गए कोष को बढाना पड़ता है
> - **NOTE** – 1000 रुपये के नोटों का परिचालन 8 नवम्बर, 2016 से बंद हो गया है।

NOTE- सिक्के सीमित विधि ग्राह्य (Limited Legal Tender) है । भारत में कागजी नोट असीमित विधि ग्राह्य (Unlimited Le gal Tender) है । इसका अर्थ यह है कि भुगतान का निपटारा करने के लिए सिक्कों का प्रयोग केवल एक सीमा तक ही किया जा सकता है । इसके विपरीत , कागजी नोटों के रूप में भुगतानों का निपटारा करने हेतु उनका प्रयोग असीमित मात्रा में किया जा सकता है ।

सिक्कों का उत्पादन

- सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की पाँच टकसालें मुम्बई , अलीपुर (कोलकाता) , सैफाबाद (हैदराबाद), चेर्लापल्ली (हैदराबाद) तथा नोएडा में स्थित है।
- टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है।
- **NOTE**- 25 पैसे तथा इससे कम मूल्य के सभी सिक्कों का परिचालन जुलाई, 2011 से बंद हो गया है । अर्थात देश में अब 50 पैसे का सिक्का सबसे कम मूल्य की विधिग्राह्य मुद्रा है ।

1. इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस , नासिक (महाराष्ट्र) –

- भारत प्रतिभूति में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक -भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर - अदालती स्टाम्पों, बैंकों (RBI तथा SBI) के चेकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों , वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है ।

(A) परिमाणात्मक विधियाँ

- इनके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा पूर्ति / साख को प्रभावित किया जा सकता है । इनके द्वारा साख के प्रवाह को न तो अर्थव्यवस्था के किसी खास क्षेत्र की ओर निर्देशित किया जाता है और न ही सीमित किया जाता है । ये विधियाँ निम्न हैं-

बैंक दर	• भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यावसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, बैंक दर कहलाता है । • **प्रभाव-** बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक बैंकों द्वारा आवंटित ऋणों की ब्याज दर पर पड़ता है । इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों की कुल वैधानिक जमाराशि के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर उनके मूल कोटे निर्धारित कर दिया गया । • निर्धारित कोटे की सीमा तक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण लिया जा सकता है । इससे अधिक ऋण देने पर बैंक दर के अतिरिक्त ब्याज की दंड दर (Penal rate) देनी पड़ती है । • बैंक दर में वृद्धि या कमी व्यावसायिक बैंक द्वारा आवंटित ऋणों पर ब्याद दर कम या ज्यादा करने के लिए होता है । • **NOTE :** बेस रेट वह दर है जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसी भी तरह का ऋण नहीं दे सकते हैं । यह वर्ष 2010 में पूर्व प्रचलित प्राइम लैंडिंग रेट नोट (PLR) के स्थान पर अपनाया गया है
नकद आरक्षण अनुपात	• प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी कुछ जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास सदैव नकद रूप में रखता है जिसे नकद आरक्षण अनुपात (CRR) कहते हैं । • रिजर्व बैंक इस नकद पर कोई ब्याज बैंक को नहीं देता है । जब रिजर्व बैंक साख मुद्रा वृद्धि करना चाहता है , तो वह इस अनुपात में कमी कर देता है । और यदि वह साख मुद्रा में कमी करना चाहता है , तो वह इस अनुपात में वृद्धि कर देता है ।
वैधानिक तरलता अनुपात	• प्रत्येक बैंक को कुल जमाराशि के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में या अन्य तरल परिसम्पत्तियों के रूप में (सोना अनुमोदित प्रतिभूतियाँ- सरकारी प्रतिभूतियाँ) रखना पड़ता है जिसे वैधानिक तरलता (SLR) कहा जाता है । • यदि रिजर्व बैंक को साख मुद्रा का प्रसार करना होता है , तो इस अनुपात को कम कर दिया जाता है , ताकि बैंकों के पास तरल कोषों में वृद्धि हो सके । • यदि साख का संकुचन करना होता है , तो इस अनुपात को बढ़ा दिया जाता है , ताकि बैंकों के पास तरल कोष कम उपलब्ध हो ।
रेपो दर	• रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है । • इसका प्रभाव व्यावसायिक बैंकों द्वारा आवंटित ऋणों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है । • इसका प्रयोग तात्कालिक मुद्रा के प्रसार में वृद्धि या कमी के लिए किया जाता है । • मंदी के दौरान रेपो दर में कटौती की जाती है ताकि मुद्रा के प्रसार में वृद्धि हो। ज्यों - ज्यों मंदी का दौर खत्म होता है , रेपो दर से वृद्धि की जाती है ताकि तात्कालिक मुद्रा का प्रसार कम हो ।
रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)	• यह रेपो दर से उल्टी होती है । बैंकों के पास दिनभर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है । बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाए रिजर्व बैंक में रख सकते हैं , जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है । जिस दर पर यह ब्याज मिलता उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं ।
मार्जिनल स्टैण्डिंग फैसिलिटी (MSF)	• इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक । दिन (24 घण्टे) हेतु ऋण प्राप्त कर सकते हैं । • MSF के माध्यम से बैंक अपनी NDTL के 2.5% तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। • इसमें SLR में रखी प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकते हैं । • यह सुविधा मात्र वाणिज्यक बैंकों को उपलब्ध है । MSF की ब्याज दर Repo rate से 0.25 % अधिक होती

- आम बजट एवं रेल बजट को अलग - अलग प्रस्तुत करने की यह प्रक्रिया 92 वर्षों तक जारी रही और अंततः बजट 2017-18 में इन दोनों का विलय कर दिया गया।

बजट 2023-24

2023-24 का बजट अनुमान

- कुल प्राप्तियां (उधारी के अलावा)- 27.2 लाख करोड़
- कुल व्यय - 45 लाख करोड़
- नेट टैक्स प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़

बजट 2023 की खास बातें

- भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 लाख रु. हुई।
- अगले एक साल तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी।
- पीएम सुरक्षा के तहत् 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा।
- बागवानी योजनाओं पर रहेगा जोर, 2200 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान।
- कृषि के लिए कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड रुपए किया जाएगा।
- 157 नर्सिंग कॉलेज देश के अलग-अलग हिस्सों में खोले जाएंगे।
- अनुसूचित जाति मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ खर्च होंगे।
- पीएम आवास योजना फंड में 66 फ़ीसदी की बढ़ोतरी।

बजट 2023 में क्या हुआ सस्ता और महंगा?

- सस्ता - इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, साइकिल, लिथियम बैटरी, हीरे के आभूषण।
- महंगा:- सोना, आयातित चाँदी, प्लेटिनम, विदेशी किचन चिमनी, सिगरेट।

Note:- 2023-24 का बजट अमृत काल में पहला बजट है।

- बजट: व्यय, कर, लेन- देन और योजनाओं का ब्लूप्रिंट हैं।
- संविधान के अनुच्छेद- 112 में बजट शब्द का उपयोग न करते हुए इसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है।
- यह बजट आगामी वर्ष 2023- 24 के लिए पेश किया गया है।
- वर्ष 2022- 23 में भारत की विकास दर 7% के आस-पास रही है, जो दूसरे देशों की तुलना में बहुत बेहतर है, क्योंकि ऐसी महामारी कोविड-19 और वैश्विक मंदी जो रही है।
- वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत रखा गया था। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक सफल रही है।
- वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.9 प्रतिशत रखा गया है और इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2023-24 का बजट 7 मूल आधारों पर आधारित है, जिसे सप्त ऋषि- 7 कहा गया है।
  1. समावेशी विकास –
  (a)कृषि (b)स्वास्थ्य क्षेत्र (c)शिक्षा क्षेत्र
  2.वित्तीय क्षेत्र
  3.युवा शक्ति
  4.आखिरी व्यक्ति तक पहुंच
  5. अवसंरचना निवेश
  6. सक्षमता का विकास
  7. हरित विकास

  कृषि और सहकारिता:- ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि
- उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम
- भारत को श्री अन्न देने के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
- पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य।
- भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सहयोग।
- भारत मिलेट (बाजरा) को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है।

❖ **स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि:-** वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत।

- वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए **उन्मूलन मिशन** की शुरुआत।
- चुने हुए ICMR लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सीय अनुसंधान को प्रोत्साहन।
- फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत।

❖ **<u>आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना</u>** : "कोई पीछे न छूटे"

- प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुआत।
- कर्नाटक के सूखा संभाव्य क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता।
- 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 से अधिक शिक्षकों की भर्ती।
- PMGKAY के तहत्, सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
- प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए 'भारत श्री' योजना की शुरुआत।

राजनीतिक रूप से प्रशासित कीमतें	बड़े पैमाने पर बाजार द्वारा निर्धारित कीमतें
राज्य नेतृत्व आर्थिक वृद्धि	बाजार - निर्धारित आर्थिक वृद्धि
घाटे के लिए ज्यादा चिन्ता की बात नहीं।	सभी प्रकार के घाटे उपस्थित।
मुद्रास्फीति की प्रक्रिया द्वारा **विकास**	लक्षित मौद्रिक और **राजकोषीय** नीतियाँ

निजीकरण	**निजीकरण**
सार्वजनिक उपकरण विकास में इंजन के रूप में।	निजी निवेश विकास के इंजन के रूप में
राज्य का बार-बार हस्तक्षेप	राज्य का चयनात्मक और प्रभावी हस्तक्षेप
सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों का प्रभुत्व	निजी हित के क्षेत्रों से **निकासी**
एकाधिकार की अवधारणा	सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बीच अन्तर को कम करना।

वैश्वीकरण

बन्द अर्थव्यवस्था - खुली अर्थव्यवस्था
आत्मनिर्भर - विश्व बाजारों के साथ एकीकरण
आयात प्रतिस्थापन - निर्यात उन्मुख रणनीति रणनीतियाँ
FDI और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर प्रतिबंध - FDI और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सुविधाएँ

अध्याय – II
मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास

मानव विकास सूचकांक

- मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI) की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) से सम्बद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब - उल - हक तथा अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री एस.के. सेन तथा सिगर हंस ने किया ।
- मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य , शिक्षा व आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी (UNDP) का सूचकांक है ।
- HDI का अधिकतम मूल्य 1 था न्यूनतम मूल्य 0 होता है ।
  1. जीवन प्रत्याशा सूचकांक (Life - expectancy Index)
  2. शिक्षा सूचकांक (Education Index)
  3. जीवन निर्वाह का स्तर (Standard of Living) जिसमें क्रय - शक्ति समायोजित प्रतिव्यक्ति आय (डॉलर) में व्यक्त करते हैं ।
- सभी मिलकर मानव विकास सूचकांक का निर्माण करते हैं । इस प्रकार , मानव विकास सूचकांक = 1/3 (जीवन प्रत्याशा सूचकांक शिक्षा सूचकांक + GDP सूचकांक)
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने इस अवधारणा को अपनाया तथा पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया।
- **सूचकांक का मापन**
  (i) अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश का मापन 0.800 एवं इससे अधिक
  (ii) उच्च मानव विकास वाले देश का मापन 0.701 एवं इससे अधिक
  (iii) मध्यम मानव विकास वाले देश का मापन 0.550 एवं इससे अधिक
  (iv) निम्न मानव विकास वाले देश का मापन 0.352 एवं इससे अधिक

मानव विकास रिपोर्ट (Humen Develpment Report- HDR) 2020

➢ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट (Humen Development Report- HDR) 2020 के अनुसार, मानव विकास सूचकांक ((Human Development Index- HDI) में भारत131वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पर था।

- वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में 189 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक (HDI) की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है।
- HDR 2020 में पृथ्वी पर दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक को पेश किया गया है, जो देश के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा सामग्री के पदचिह्न (Footprint) द्वारा मानक मानव विकास सूचकांक (HDI) को समायोजित करता है।
- अन्य सूचकांक जो इस रिपोर्ट का ही भाग हैं, इस प्रकार हैं:

❖ असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (Inequality adjusted Human Development Index-IHDI)
❖ लैंगिक विकास सूचकांक (GDI),
❖ लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)
❖ बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI).

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- HDI इस बात पर ज़ोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिये वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिये, न कि केवल आर्थिक विकास को।
- मानव विकास तीन बुनियादी आयामों पर आधारित होता है:

✓ लंबा और स्वस्थ जीवन,
✓ ज्ञान तक पहुँच,
✓ जीने का एक सभ्य मानक।

वर्ष 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्त्ता:

- नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष पर है, इसके बाद आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हॉन्गकॉन्ग और आइसलैंड का स्थान है।

एशियाई क्षेत्र की स्थिति:

- वैश्विक सूचकांक में "बहुत उच्च मानव विकास" के साथ एशियाई देशों के मध्य शीर्ष स्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए सिंगापुर 11वें, सऊदी अरब 40वें और मलेशिया 62वें स्थान पर थे।
- शेष देशों में से श्रीलंका (72), थाईलैंड (79), चीन (85), इंडोनेशिया और फिलीपींस (दोनों 107) तथा वियतनाम (117) "उच्च मानव विकास" वाले देशों की श्रेणी में थे।
- 120 से 156 रैंक तक भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केन्या और पाकिस्तान "मध्यम मानव विकास" श्रेणी वाले देशों में शामिल थे।

भारत की स्थिति:

- **संपूर्ण प्रदर्शन:** वर्ष 2019 के लिये HDI 0.645 है, जो देश को 'मध्यम मानव विकास' श्रेणी में तथा 189 देशों में 131वें स्थान पर रखता है।
- वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत का HDI मान 0.429 से बढ़कर 0.645 हो गया है, यानी इसमें 50.3% की वृद्धि हुई है।
- **लंबा और स्वस्थ जीवन:** वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी, जो दक्षिण एशियाई औसत 69.9 वर्षों की तुलना में थोड़ी कम थी।
- वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्ष की वृद्धि हुई है।

ज्ञान तक पहुँच:

- भारत में स्कूली शिक्षा के लिये प्रत्याशित वर्ष 12.2 थे, जबकि बांग्लादेश में 11.2 और पाकिस्तान में 8.3 वर्ष थे।
- वर्ष 1990 और 2019 के बीच स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित औसत वर्षों में 3.5 वर्ष की वृद्धि हुई तथा स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित अनुमानित वर्षों में 4.5 वर्ष की वृद्धि हुई।
- **जीने का एक सभ्य मानक:** प्रति व्यक्ति के संदर्भ में सकल राष्ट्रीय आय (GNI) पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट के बावजूद वर्ष 2019 में कुछ अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है।
- वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत के प्रति व्यक्ति GNI में लगभग 273.9% की वृद्धि हुई है।

ग्रहीय दबाव-समायोजित HDI/प्लैनेटरी प्रेशर-एडजस्टेड HDI (PHDI)

- PHDI प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और मैटेरियल पदचिह्न (Material Footprint) के मानक HDI को समायोजित करता है।

देशों का प्रदर्शन:

- नॉर्वे जोकि HDI में शीर्ष स्थान पर है, यदि PHDI मीट्रिक में इसका आकलन किया जाए तो यह 15 स्थान नीचे पहुँच जाएगा, आयरलैंड इस तालिका में शीर्ष पर है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (HDI रैंक -17) और कनाडा (HDI रैंक -16) प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हुए PHDI में क्रमशः 45वें और 40वें स्थान पर पहुँच जाएंगे।
- तेल और गैस से समृद्ध खाड़ी राज्यों के स्थान में भी गिरावट आई है। चीन अपने मौजूदा 85वें स्थान से 16 स्थान नीचे आ जाएगा।

भारत का प्रदर्शन:

- PHDI में आकलन करने पर भारत रैंकिंग में आठ स्थान ऊपर आ जाएगा।
- पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन क्षमता को वर्ष 2005 के स्तर से

- ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, ईडब्ल्यूएस नहीं माना जायेगा, भले ही परिवार की आय आठ लाख रुपये से कम हो:
- 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि।
- 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रें में आवासीय, 200 वर्ग गज और उससे अधिक का भूखंड।
- इस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया, जिसने आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के बीच सामाजिक एकीकरण को संभव बनाया है।

बिहार की अर्थव्यवस्था

अध्याय- 1

अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन

बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में अच्छी वापसी की। त्वरित अनुमान के अनुसार, स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 2020-21 के (-) 3.2 प्रतिशत की तुलना में 10.98 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68 प्रतिशत थी।

- बिहार देश का अपेक्षाकृत कम आय वाला राज्य है। त्वरित अनुमान के अनुसार, 2021-22 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,75,448 करोड़ रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,28,065 करोड़ रु. था।
- 2021-22 में राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,14,431 करोड़ रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,82,274 करोड़ रु. था।
- फलतः बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 54,383 रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 34,465 रु. था।
- प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले दो उप-क्षेत्र 'पशुधन' और 'मत्स्याखेट एवं जलकृषि' हैं जिनकी वृद्धि दरें 2017-18 और 2021-22 के बीच क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत रही हैं।
- हालांकि 'खनन एवं उत्खनन' क्षेत्र में भी 90 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई है। द्वितीयक क्षेत्र में 'विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं (ईजीडब्ल्यूयूएस) में 2017-18 और 2021-22 के बीच 14.5 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई।
- 2017-18 और 2021-22 के बीच तृतीयक क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र वायु परिवहन (10.5 प्रतिशत), भंडारण (21.3 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं (12.6 प्रतिशत) और लोक प्रशासन (9.3 प्रतिशत) थे।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रमुख क्षेत्रों के हिस्से के लिहाज से देखें, तो 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 के 21.4 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 21.2 प्रतिशत रह गया।
- द्वितीयक क्षेत्र में भी थोड़ी गिरावट आई जो 2020-21 के 19.3 प्रतिशत से 2021-22 में 18.1 प्रतिशत रह गया।
- वहीं, 2020-21 और 2021-22 के बीच तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 59.3 प्रतिशत से बढ़कर 60.7 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में तीन सबसे समृद्ध

त्वरित अनुमान के अनुसार, 2021-22 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 के 587.15 हजार करोड़ रु. की तुलना में 675.45 हजार करोड़ रु. था। इसका अर्थ 15.0 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि 2020-21 में वृद्धि मात्र 0.8 प्रतिशत थी।

वहीं, 2021-22 में वर्तमान मूल्य बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 54,383 रु. था जो 2020-21 के 47,983 रु. 13.3 प्रतिशत अधिक था।

बिहार का राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

	राज्य घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रु.)			वृद्धि दर	
	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)					
(i) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर	398.28	385.73	428.06	-3.2	11.0
(ii) वर्तमान मूल्य पर	582.52	587.15	675.45	0.8	15.0
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)					
(i) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर	33036	31522	34465	-4.6	9.3
(ii) वर्तमान मूल्य पर	48318	47983	54383	-0.7	13.3
निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)					
(i) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर	359.20	344.18	382.27	-4.2	11.1
(ii) वर्तमान मूल्य पर	533.23	533.58	614.43	0.1	15.2
प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)					
(i) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर	29794	28127	30779	-5.6	9.4
(ii) वर्तमान मूल्य पर	44230	43605	49470	-1.4	13.5

टिप्पणी : 2020-21 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2021-22 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।
स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 428.06 हजार करोड़ रु. तक पहुंच जाने की संभावना है जो 2020-21 के 385.73 हजार करोड़ रु. से 11.0 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2019-20 से 2020-21 के बीच वृद्धि दर निश्चित रूप से ऋणात्मक (-3.2 प्रतिशत) थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में स्थिर मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद 8.7 प्रतिशत बढ़ा ।

वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 382.27 हजार करोड़ रु. था, जिसके आधार पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 30,779 रु. होता है। वहीं, वर्तमान मूल्य पर 2021-22 में अनुमानित निवल राज्य घरेलू उत्पाद 614.43 हजार करोड़ रु. है, जिससे प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 49,470 रु. होता है।

राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत के विभिन्न राज्यों के लिए 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान नियमित रूप से प्रकाशित करता है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जबकि इस अवधि में संपूर्ण भारत के लिए वृद्धि दर मात्र 0.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2021-22 में राज्य का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 के 28,127 रु. से 9.4 प्रतिशत बढ़कर 30,779 रु. हो गया । वर्ष 2020-21 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (28,127 रु.) राष्ट्रीय औसत (85,110 रु.) का मात्र 33.1 प्रतिशत था । यह अनुपात 2021-22 में बढ़कर 33.7 प्रतिशत हो गया है

अध्याय - 3

कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

अपनी प्रचुर अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कड़ियों के कारण कृषि का विकास बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत थी । कुल मिलाकर, 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में इस क्षेत्र का 20 प्रतिशत हिस्सा था।

- वर्ष 2021-22 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि के उप-क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार था फसल क्षेत्र 11.1 प्रतिशत, पशुधन 6.6 प्रतिशत, और मत्स्याखेट एवं जलकृषि 1.8 प्रतिशत ।
- वर्ष 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.5 प्रतिशत था जबकि फसल सघनता 1.44 थी। वहीं, 2021-22 में राज्य में कुल 181.0 लाख टन अनाजों का उत्पादन हुआ।
- गन्ना विभाग के अनुमान के अनुसार, राज्य में 2021-22 में कुल 119.77 लाख टन ईख का उत्पादन हुआ जबकि उत्पादकता 49.70 टन प्रति हेक्टेयर थी।
- राज्य सरकार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति का क्रियान्वयन कर रही है, जिसमें कृषि आधारित नए उद्योगों की स्थापना या मौजूद इकाइयों के क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए व्यक्तिगत निवेशकों को 15 प्रतिशत और कृषि उत्पादक कंपनियों को 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही हैं।
- इस पहल के लिए चिन्हित सात केंद्रित उत्पाद मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय हैं।
- डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए मक्का और धान के संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कृषि विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत कुल 142.27 लाख रु. के व्यय से एक नई योजना शुरू की गई है।
- जैविक और टिकाऊ खेती राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए जैविक कॉरीडोर योजना (2022-25) के तहत और भी 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है।
- वहां किसानों को सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के लिहाज से अधिसंरचना सहायता दी जा रही है और लॉजिस्टिक सहयोग के रूप में तापरोधी / रेफर वैन, स्मार्ट जैविक मंडी, पथ विक्रय, मंडियों में जगह आवंटित करने में कृषक उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता, जैविक मूल्यश्रृंखला का विकास आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- वर्ष 2021-22 तक लगभग 17,534 भूखंड प्रमाणन के अंतर्गत हैं।
- वर्ष 2021-22 में सिंचाई विकास का कुल व्यय 2670.49 करोड़ रु. था। जल संसाधन विभाग द्वारा वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत मार्च 2022 तक लगभग 37.22 लाख हे सिंचाई सुविधा सृजित की गई थी।
- 405.66 करोड़ रु. के व्यय से कमला नदी पर बैराज का निर्माण प्रगति पर है और उसे मार्च 2023 तक पूरा हो जाने का अनुमान है। वर्तमान कृष्य कमांड क्षेत्र 28,384 हेक्टेयर है और इस बैराज से 1175 हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुड़ जाने के बाद कुल कृष्य कमांड क्षेत्र 29,559 हे. हो जाएगा।

भूमि का उपयोग

बिहार देश के पूर्वी क्षेत्र का राज्य है। इसका क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है जो देश के कुल भूक्षेत्र का लगभग 3 प्रतिशत है। वहीं, देश की कुल आबादी में राज्य का 8.6 प्रतिशत हिस्सा है। जहां राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, वहीं बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। फलतः राज्य में जमीन की सीमित आपूर्ति के कारण काफी दबाव बनता है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के बीच भूमि उपयोग का पैटर्न तालिका में प्रस्तुत है।

बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न (2020-21)

(प्रतिशत में)

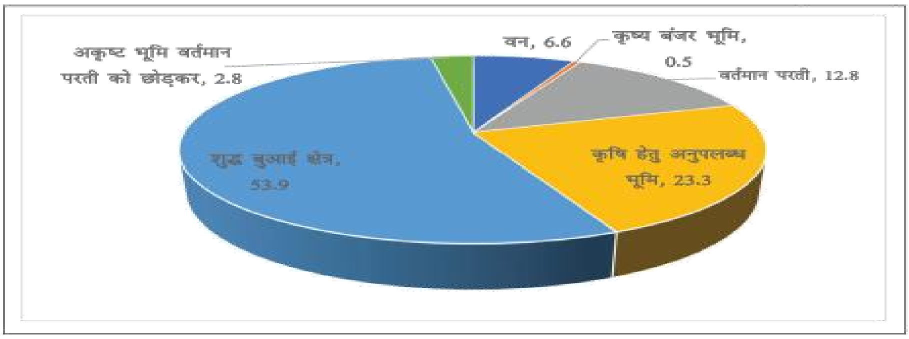

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856WI8&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्तूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
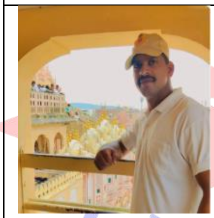	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.-Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota

And many others……

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/paxqem

Online order करें – https://shorturl.at/hitzF

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO